

प. बंगाल में वामपंथी सरकार के 1970 के दिनों से ही वोटर लिस्ट में हेराफेरी चुनाव प्रक्रिया का अंग बन चुकी है

ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कार फैक्ट्री के लिए भूमि अधिग्रहण को मुद्दा बनाकर वोटर लिस्ट की हेराफेरी की स्थापित व्यवस्था को बदल दिया था

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। सारी जिंदगी एक मजबूत और आक्रामक राजनीतिक लड़ाकू रही ममता बनर्जी इस बार खुद को सम्भवतः कुछ मुश्किल स्थिति में महसूस कर रही हैं। मतदाता सूची की जो गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है, वह ममता बनर्जी की जीत की रणनीति को सीधे चुनौती दे रही है। उनके वोट बैंक के कई बड़े हिस्से अब उजागर होने और हटाए जाने के खतरे में हैं।

चुनाव परिणामों पर एसआईआर का संभावित असर देखते हुए, ममता बनर्जी अब पूरी ताकत से इस पुनरीक्षण

- अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने लोकसभा में कई बार हल्ला किया था, पर, अब यही बांग्लादेशी उनकी वोटों की हेराफेरी के मुख्य आधार हैं।
- ममता बनर्जी के बाहुबली, जिनका चित्रण सोशल मीडिया पर बहुत विस्तार से देखा जा सकता है, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि विपक्ष को कोई मतदान न कर सके।
- इन बाहुबलियों को पूर्ण प्रशासनिक सहयोग मिलता है, इसीलिए ममता बनर्जी, बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी न हो सके, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, करेंगी।
- एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बेचैन होती जा रही है।

प्रक्रिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही है और किसी तरह इसे रोकने के तरीके खोज रही है। लेकिन इसके लिये अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि

एसआईआर प्रक्रिया गति पकड़ चुकी है और काफी प्रभावी तरीके से चल रही है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां 1970 के दशक के मध्य

से सदैव ही होती रही हैं, जब से लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल में चुनावी प्रक्रिया पर दबदबा बनाया था। ममता बनर्जी ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हमारी आवाज़ बंद नहीं होगी’

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 नवम्बर। जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए.) ने आज दावा किया कि जम्मू में कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर मोरे गये छापे के दौरान एके-47 राइफलें और अन्य हथियार व गोलाबारूद बरामद किए गए, जबकि अखबार के मालिकों ने इन आरोपों को निन्दा करते हुये इन्हें “डराने, बदनाम करने और अंततः चुप कराने की कोशिश” बताया।

अधिकारियों ने कहा कि अखबार और उसके संचालकों के खिलाफ दर्ज हुये एक केस के बाद, एसआईए की टीम ने अखबार के दफ्तर और कंप्यूटरों की

- कश्मीर टाइम्स ने समाचार पत्र के कार्यालय से हथियार बरामद होने के आरोप को बेबुनियाद बताया।

पूरी तलाशी ली। अधिकारियों ने कहा कि छापे में एजेंसी ने एके राइफलों के कारतूस, कुछ पिस्तौल के राउंड और हैंड ग्रेनेड के पिन सहित, इसी प्रकार की कई अन्य चीजें ज़ब्त कीं। उन्होंने कहा कि प्रकाशन के संचालकों से पूछताछ की जा सकती है।

कश्मीर टाइम्स प्रबंधन ने अखबार के जम्मू दफ्तर पर छापे की कड़ी आलोचना की और राज्य-विरोधी गतिविधियों के आरोपों को एक स्वतंत्र (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में आजमाये गये फार्मूले को यूपी. में दोहराने की तैयारी में है भाजपा

यूपी. के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो स्वयं कुर्मी हैं, को बिहार में 25 सीटों पर कुर्मी मतदाता का मन व सोच जानने के लिए छोड़ा गया था

- यूपी. में कुर्मी जनसंख्या बिहार से दोगुनी है, पर, कुर्मी और ईबीसी सपा का वोट बैंक रहे हैं।
- भाजपा इस वोट बैंक को अपने पक्ष में जोड़ने के लिए कुर्मी/ईबीसी मुख्यमंत्री बनाने का सोच रही है।
- वैसे भी कहा जाता है कि अमित शाह व मोदी पूर्णतः खुश नहीं हैं, योगी आदित्यानाथ के काम करने के तरीके से।
- पंद्रह महीने बाद यूपी. में भी विधानसभा चुनाव होंगे, पर, क्या आसानी से बिहार का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला यूपी. में लागू कर लेगी भाजपा।

नवंबर को नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के शपथ लेने के बाद यह साफ़ होता जा रहा है कि (जदयू) नेता और भाजपा, दोनों ने अपनी राजनीतिक रणनीति सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि पड़ोस के बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सोच-समझकर बनाई है। यूपी विधानसभा चुनाव अब सिर्फ 15 महीने दूर है और इन चुनावों ने भाजपा की दीर्घ अवधि की योजना को अभी से नया आकार देना शुरू कर दिया है।

पिछले एक साल से भाजपा ने अपने ज्यादातर राजनीतिक संसाधन बिहार पर लगाए हुए थे और पार्टी, जरूरत पड़ने पर, अकेले लड़ने की स्थिति के लिए भी पूरी तरह तैयार थी। इसके साथ ही, पार्टी नेतृत्व को पूरा भरोसा था कि केन्द्र में मोदी सरकार से लगातार मिल रहे सहयोग को देखते हुए नीतीश कुमार अचानक अपनी

राजनीतिक दिशा नहीं बदलेंगे। एक अहम कदम उठाते हुये, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रचार अभियान के दौरान बिहार की जातीय गणित को करीब से देखने की जिम्मेदारी दी। बताया जाता है कि मौर्य, जो कुर्मी समुदाय के काफ़ी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, को लगभग 75 सीटों

की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी, जहाँ वे वोटर व्यवहार और ओबीसी मतदाताओं की चुनावी गतिविधियों और तौर-तरीकों की मॉनिटरिंग कर सकें। उनकी तेनाती रणनीतिक थी: कुर्मी समुदाय, जो बिहार के ओबीसी वोटों का लगभग 9 से 10 प्रतिशत हिस्सा है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

थरूर ने अपनी पुस्तकों में मोदी की काफी आलोचना की है

किताबों के अनुसार, मोदी ने प्रजातंत्रीय ढाँचे को कमज़ोर किया है व देश की इकॉनमी को हानि पहुँचा रहे हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हालिया भाषण की प्रशंसा करने के बाद, कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, खासकर केरल में, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन असली सवाल यह है: कांग्रेस नेतृत्व थरूर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या इसकी वजह यह है कि थरूर केरल की राजनीति में कांग्रेस की सेंटर-राइट स्पेस को बनाए रखने में मदद करते हैं? या फिर कांग्रेस उच्च नेतृत्व ऐसे समय में राज्य इकाई में खलबली नहीं मचाना चाहता, जब विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं। थरूर की हालिया टिप्पणियाँ दिलचस्प विरोधाभास दिखाती हैं। अपनी किताबों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तोखा हमला किया है, लोकतांत्रिक

- पर, हाल ही में उन्होंने मोदी को बधाई दी, उनके इकोनॉमिक सोच व सांस्कृतिक सामंजस्य बैठाने के लिए।
- पर, इस खुली प्रशंसा के बावजूद कांग्रेस थरूर पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही, क्या थरूर केरल में कांग्रेस को सेंटर “राइट” जगह बनाने में मदद कर रहे हैं, अपने उद्गारों से।
- या कांग्रेस केरल में चुनाव के पहले पार्टी में कुछ उथल-पुथल नहीं होने देना चाहती, थरूर को निकालित करके।

संस्थाओं को कमज़ोर करने का आरोप लगाया, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बात कही, और उन पर स्वयं को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। लेकिन कई मौकों पर उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की है, जैसे विरासत संरक्षण और वैश्विक प्रतिष्ठा के मामले में। कुछ समय पहले उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता

लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा की भी तारीफ की थी। थरूर ने राजनीति में “नैपो किड कल्चर” की आलोचना करके पार्टी के समर्पित नेताओं को भी नाराज़ कर दिया है, जिसे गांधी परिवार पर परोक्ष हमले के रूप में देखा गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आतंकी ज्यादा खतरनाक होते हैं’

नई दिल्ली, 20 नवंबर। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों को देश की आजादी पर हमला और सरकार बदलने की सोची-समझी साजिश करार दिया और उमर खालिद, शरजील इमाम समेत, कई एक्टिविस्ट्स की जमानत याचिकाओं का गुरुवार को कड़ा विरोध

- दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता की जमानत याचिका का विरोध किया।

किया। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए धमाके का हवाला देते हुए कहा कि जब पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं, तो वे जमीनी कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लैपर्ड ने सिविल लाइंस में हड़कंप मचाया

गुरुवार की सुबह 9 बजे लैपर्ड मंत्री सुरेश रावत के घर व टाइनी ब्लॉसम्स स्कूल में घुसा

जयपुर, 20 नवम्बर। राजधानी के वीवीआईपी इलाके में गुरुवार सुबह लैपर्ड के आ जाने की सूचना पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद जयपुर के पॉश इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लैपर्ड आने की जानकारी लोगों को सुबह 9 बजे मिली। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मोबाइल के जरिए एक दूसरे को इस घटना की जानकारी दी और स्थानीय लोग अपने-अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर अंदर ही दुबके रहे। वहाँस्थित स्कूलों में डर के चलते स्कूल प्रशासन ने छोटे-छोटे बच्चों को क्लास रूम में बंद कर दिया। लैपर्ड सुबह करीब 9 बजे सबसे पहले लेन नंबर 6 पर बने एक घर में घुसा और कुछ देर घूमने के बाद दीवार फांदकर मूवमेंट करता रहा। वीवीआईपी इलाके में लैपर्ड घुसने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग



जयपुर के वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस में गुरुवार को घुसा लैपर्ड बंगलों की दीवार के पीछे छुपता रहा।

लैपर्ड इलाके के एक से दूसरे घर में दीवार फांदकर मूवमेंट करता रहा। वीवीआईपी इलाके में लैपर्ड घुसने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग

की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन वन विभाग की कार्रवाई के दौरान ऐसा लगा, जैसे वो इस कार्यवाही का आदी हो और बार-बार वन विभाग की टीम को गच्चा

- स्कूल प्रशासन ने छोटे बच्चों को क्लास रूम में बंद कर दिया। दो घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम लैपर्ड को ट्रैकुलाइज कर पाई।

देकर अपनी जगह बदलता रहा। लेकिन वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 11 बजे सिविल लाइंस की लेन - 6 से लेपर्ड को ट्रैकुलाइज कर लिया, जिसके बाद उसे झालाना रिजर्व ले जाया गया।

बताया जा रहा है कि वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस में राजभवन, सीएम आवास समेत, कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास हैं, जहां लेपर्ड की सूचना से हड़कम्प मचा रहा। दो घंटे बाद लेपर्ड को रेस्क्यू किए जाने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

पंजाब पुलिस ने लुधियाना में दो आतंकियों का एनकाउंटर किया

लुधियाना, 20 नवंबर। लुधियाना में पंजाब पुलिस ने दो आतंकियों का एनकाउंटर किया है, दोनों आतंकियों के तार आतंकी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का है।पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन

- दोनों संदिग्ध लोग हैंड ग्रेनेड तय शुदा जगह फेंकने की फिराक में थे।

दोनों संदिग्ध लोगों को हैंड ग्रेनेड इकट्ठा करके तयशुदा जगहों पर फेंकने का काम सौंपा गया था। पुलिस ने समय रहते इन्हें धर दबोचा है। पुलिस ने मौके से हैंड ग्रेनेड, कुछ पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार, एनकाउंटर की ये घटना लुधियाना शहर से बाहर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास हुई। अगर पकड़े जा जाते तो ये दोनों आतंकी किसी बड़ी घटना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 नवंबर। लाल किले के पास हुए विनाशकारी कार विस्फोट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, एक नाम इसके केन्द्र में उभरकर सामने आया है: डॉ. उमर उन-नबी (कुछ रिपोर्टों में उमर मोहम्मद), एक कश्मीरी डॉक्टर, जिन पर अब भारतीय एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक सॉफिस्टिकेटेड “वाइट-कॉलर” आतंकी मॉड्यूल का प्रमुख ऑपरेटिव होने का आरोप लगाया है। सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लाल किले के पास

जिस हद्दई आई-20 कार में धमाका हुआ, उसे उमर ही चला रहे थे। जांचकर्ता इस घटना को किसी हादसे की तरह नहीं, बल्कि कार से किए गए सुसाइड अटैक की तरह देख रहे हैं। फॉरेंसिक और डीएनए टीमें मलबे से मिले अवशेषों की पहचान की पुष्टि में लगी हैं। डॉ. उमर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के कोइल गांव के रहने वाले हैं, जहां सुरक्षा बलों ने जांच के सिलसिले में उनका घर गिरा दिया। कई मीडिया स्रोतों के मुताबिक, उनका जन्म 24 फरवरी 1989 को हुआ था। वे उस पीढ़ी के पढ़े-लिखे कश्मीरियों में आते

- उन्होंने पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बम बनाने की प्रक्रिया सीखी तथा फरीदाबाद के मकान में उसका एक्सपैरीमेंट करते रहे।
- उमर के व्यक्तित्व का बहुत बारीकी से अध्ययन हो रहा है, यह जानने के लिए कि कैसे आतंकवादी विचारधारा डॉक्टरों के पढ़े लिखे दिमाग में स्थान बना रही है।
- जाँच एजेंसियाँ इस पूरे प्रकरण का वॉटर टाइट केस बनाने में तो जुटी हैं ही, पर, उनके समक्ष एक चुनौती यह भी है कि कैसे ऐसे मॉड्यूल्स को पहचानें और पनपने से पहले ही रोक लें।

हैं, जिनकी प्रोफेशनल पहचान अब उन

पर लगे गंभीर आरोपों के बिल्कुल

विपरीत है। उनका डॉक्टर बनने का सफर जम्मू-कश्मीर से शुरू हुआ, जहां उन्होंने एम.बी.बी.एस. किया और फिर श्रीनगर के गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज से एम.डी. किया। उन्होंने अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम किया और बाद में फरीदाबाद में अल-फलाह मैडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर शामिल हुए। फरीदाबाद में वे कॉलेज के पास एक साधारण किराए के कमरे में रहते थे, जिन्हें जानने वाले शांत और पढ़ने-लिखने में लगे रहने वाला व्यक्ति बताते हैं। अधिकारियों के अनुसार, उमर

अकेले काम नहीं कर रहे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वे डॉक्टरों, छात्रों और स्टाफ का एक ऐसा मॉड्यूल चला रहे थे, जो कथित तौर पर कट्टरपंथी था और जैश ए मोहम्मद (ऐ.ई.एम.) से जुड़ा हुआ था। नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों में डॉ. अदील अहमद राथर और डॉ. मुजम्मिल शाकिल शामिल हैं, जो दोनों कश्मीर के ही रहने वाले हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि उमर ने फरीदाबाद में अपने कमरे में एक गुप्त लैब बनाई हुई थी, जहां वे विस्फोटकों पर प्रयोग करते थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वे पाकिस्तान में बैठे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इनमें भाजपा के 14, जदयू के 8, लोकजनशक्ति पार्टी के 2 तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा व हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के एक-एक मंत्री थे।

(जदयू) के आठ,लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के एक-एक मंत्री शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जे. पी. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम से राजस्थान बनेगा जी.सी.सी. एक्सीलेंस हब

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदित हो चुकी है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को यहां जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करते हैं।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।

एनसीआर रिजन और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बढ़े औद्योगिक केंद्रों और बाजारों तक उपलब्ध करवा रही है। देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी सुगम बनाती है।

यह होगी आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अग्रुवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी। यह

- एनसीआर, डीएमआईसी के साथ कनेक्टिविटी से जीसीसी निवेशकों को बड़े औद्योगिक केन्द्र तथा बाजारों तक पहुंच मिलेगी
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के आवेदनों का निस्तारण भी त्वरित गति से होगा

अग्रुवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी। कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। वहीं, जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

100 अरब डॉलर का लक्ष्य

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है।

इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित

किया जाएगा।

जीसीसी स्थापना पर रिप्स का लाभ

इस नीति में जीसीसी की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इसमें परियोजना लागत (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 30 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भूमि या लीज एरिया की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति लैण्ड कॉस्ट

इंसेटिव के रूप में दी जाएगी। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन पर पहले तीन वर्षों तक 30 प्रतिशत (अधिकतम 1.25 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष) की पेरोल सब्सिडी उपलब्ध दी जाएगी। यह सब्सिडी 10 करोड़ रुपए प्रति जीसीसी प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

राजस्थान विधानसभा में विधायक अब करेंगे ‘‘डिजिटल हस्ताक्षर’’

वासुदेव देवनानी के स्पीकर बनने के बाद राजस्थान विधानसभा की डिजिटल यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ा



विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। राजस्थान विधानसभा की डिजिटल यात्रा में एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किए जा रहे नवाचारों के तहत राज्य विधानसभा सचिवालय में होने वाली समितियों की बैठकों में माननीय सदस्यों की उपस्थिति अब आईपैड पर डिजिटल रूप से दर्ज होगी। पूर्व में यह उपस्थिति हस्ताक्षर मैनुअल ढंग से दर्ज किए जाते थे।

डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा एक एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। विधानसभा के उप सचिवों और समस्त सहायक सचिवों को इस एप्लीकेशन के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही विधान सभा के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी देने के लिए एक बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है।

इसके अलावा विधानसभा की सभी समितियों की बैठकों के लिए

- डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने एक एप्लीकेशन भी तैयार की है, जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है

विधान सभा के डिजिटलाइजेशन के तहत सभी 200 माननीय सदस्यों की सीटों पर आई पेड लगाए गए हैं और विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत ई-विधान एप्लीकेशन नेवा का उपयोग राजस्थान विधान सभा को डिजिटल बनाये जाने के लिए किया जा रहा है। इससे विधान सभा के सदन से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट्स, वीडियो आदि मीडिया अनुसंधानकर्ता और आम नागरिक को अब सरलता से ऑन लाईन

उपलब्ध हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की विधान सभाओं को डिजिटल बनाए जाने के लिए वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन का उपयोग कर राजस्थान विधान सभा सदन और सचिवालय को डिजिटल किया गया है। इससे पर्यावरण की रक्षा एवं समय की बचत के लिए विधान सभा और सचिवालय की कार्यवाही पेपरलेस गई है। ई-विधान ऐप एन्ड्रायड और आई. ओ.एस दोनों तरह के मोबाइल पर संचालित हो रहे हैं। नेवा के तहत सदन की कार्यवाही विवरण, सदन में रखे जाने वाले पेपर्स, विधेयकों से सम्बन्धित जानकारी समितियों की रिपोर्ट, प्रश्न और उनके जवाब, बुलेटिन, कार्यवाही विवरण, डिजिटल लाइब्रेरी, सूचनाएं और सदस्यों से सम्बन्धित जानकारी एक ही एप्लीकेशन में उपलब्ध हो रही है। इसके साथ ही राजस्थान विधान सभा का ई-बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। साथ ही अन्य कई नवाचार भी किये गये हैं।

कांग्रेस को सता रही रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की चिंता : अशोक परनामी

‘चुनाव हारने पर पहले कांग्रेस ईवीएम का राग अलापती थी, अब एसआईआर का राग अलाप रही’



अशोक परनामी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अनावश्यक विरोध पर तिखी प्रतिक्रिया दी। परनामी ने कहा कि कांग्रेस लगातार बुरी तरह हारती जा रही है, फिर चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर बिहार चुनाव। कांग्रेस का जनाधार लगातार बुरी तरह गिरता जा रहा है। कांग्रेस पहले ईवीएम पर राग अलापती थी, सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम को छोड़कर अब एसआईआर पर राग अलापना शुरू कर दिया। हार के बाद कांग्रेसी नेता घबरा गए हैं, उन्हें उनके बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों की चिंता सता रही है।

उन्होंने कहा कि केवल विरोध करना, आंदोलन करना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष को विकास के लिए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। ऐसे में मुद्दा विहीन कांग्रेस बेवजह जनता को भ्रमित करने का कामकर रही है।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को आंदोलन करने की बजाए बिहार चुनाव में बुरी तरह हार की समीक्षा करनी चाहिए। जनता कांग्रेस के साथ नहीं, मोदी के साथ है, यह समझना चाहिए। राजधानी जयपुर में युवा कांग्रेस का तत्कालिक आंदोलन महज चंद्र मिनटों में समाप्त हो गया और फ्लोप शो शाबित हुआ। यह बताता है कि देश की जनता, युवा अब कांग्रेस के साथ नहीं है, ना ही कांग्रेस के बहकावे में आनी वाली है।

■ ‘प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा, इसलिए बेवजह जनता को भ्रमित कर रही है कांग्रेस’

है। आज डबल इंजन सरकार राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, और आने वाले तीन सालों में विकसित राजस्थान के लिए आयाम स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि, गहलोत के कार्यकाल में पेपरलीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जबकि भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गहलोत 5 साल तक ईआरसीपी पर कुंडली मारकर बैठे रहे, जबकि भजनलाल शर्मा ने इस अमृत योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए और करीबन 7 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतारे, जबकि गहलोत ने निवेश के नाम पर जनता से धोखा किया। गहलोत पूरे 5 साल अपने ही लोगों से सरकार बचाने में लगे रहे, जबकि जनता की सेवा, विकास कार्यों को उन्होंने नजर अंदाज किया। गहलोत भ्रष्टाचार में आर्कट तक डूबे हुए और होटलों से सरकार चलाते रहे। अब भजनलाल शर्मा सरकार के जनकल्याण, जनहितैषी कार्यों को गहलोत पचा नहीं पा रहे हैं। प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह

बागडी, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक और भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची उपस्थित रहे।

जंगली जानवरों द्वारा फसल नुकसान को ‘स्थानीयकृत जोखिम’ के रूप में मान्यता मिली

इसके साथ ही धान जलभराव को भी स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किया गया

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश के अननदाताओं को बड़ी सौगात दी
- इस प्रावधान का लाभ तटीय, हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के किसानों को मिलेगा

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के किसानों को होगा, जहाँ जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति एक प्रमुख चुनौती है। ज्ञात रहे कि देशभर में किसान लंबे समय से हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जंगली जानवरों के हमलों के कारण बढ़ते फसल नुकसान का सामना कर रहे हैं। यह समस्या मुख्यतः वन क्षेत्रों, त्रों वन

गलियारों और पहाड़ी इलाकों के निकट बसे किसानों में अधिक देखी जाती है। अब तक ऐसे नुकसान फसल बीमा योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी।

ऐसे में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ अब स्थानीय स्तर पर फसल नुकसान झेलने वाले किसानों की समस्याबद्ध और तकनीक-आधारित दावा निपटान का लाभ मिलेगा।

धान जलभराव को स्थानीयकृत आपदा श्रेणी में पुनः शामिल किए जाने से तटीय और बाढ़ संभावित राज्यों जैसे ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जहाँ जलभराव से धान की फसल का नुकसान हर वर्ष दोहराया जाता है।

आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव आकर बताए इंटरनेशनल प्लेयर को क्यों नहीं दी नियुक्ति?

- राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि पैरालंपिक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता की नियुक्ति की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकपक्षीय न्यायाधीश की प्रतिक्रिया के बाद जयपुर में आदेश निहाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा की गत सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से मामले में सकारात्मक निर्णय लेकर 2 सप्ताह में अदालत में जानकारी पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से तय अवधि में कोई जानकारी नहीं दी गई।

याचिका में अधिकवक्ता तनवीर अहमद ने बताया की याचिकाकर्ता 26 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट है

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाइकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट रूल्स, 2017 के तहत सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि पैरालंपिक सहित अन्य प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता की नियुक्ति की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकपक्षीय न्यायाधीश की प्रतिक्रिया के बाद जयपुर में आदेश निहाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा की गत सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से मामले में सकारात्मक निर्णय लेकर 2 सप्ताह में अदालत में जानकारी पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से तय अवधि में कोई जानकारी नहीं दी गई।

याचिका में अधिकवक्ता तनवीर अहमद ने बताया की याचिकाकर्ता 26 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट है

दिव्यांग आयोग में आबकारी विभाग ने स्वीकार किया है कि बीते तीन सालों से दिव्यांगों के लिए कोई भी पद पहचान प्रक्रिया नहीं की गई है, यह भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और धारा 34 के साथ ही इस संबंध में साल 2018 में बनाए नियमों के खिलाफ है।

याचिका के अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के समान मामले में पूर्व में अन्य पैरा एथलीट अबनी लखेरा, सुंदर गुर्जर और देवेन्द्र झाझडिया को एसीएफ के पद पर नियुक्ति दी गई थी, जबकि उस समय भी वह पद दिव्यांगों के लिए निर्धारित नहीं था। याचिकाकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, लेकिन अफसरों की उपेक्षा के कारण उसे आजीविका और सम्मान से वंचित किया जा रहा है। जिस सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को हाज़िर होकर जवाब देने को कहा है।

जयपुर (कासं)। केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए देश का माइनिंग सेक्टर नई उर्जा और गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगातार कानून कायदों को व्यावहारिक बनाने के साथ ही टाइमलाइन तय की गई है जिससे खानों की नीलामी के बाद खानों के परिचालन में लाने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि इसके लिए सरकारी स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए और एलओआई स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं।

केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल गुरुवार को आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआईधारकों से रुबर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों में एलओआई धारकों द्वारा जितनी जल्दी खानों को परिचालन में लाया जाएगा उतना ही अधिक लाभ खानधारकों को होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोत्साहन के प्रावधान किये गये हैं।

गोयल ने राजस्थान में मेजर मिनरल माइंस के ऑक्शन और प्री एम्बेडेड खानों की ऑक्शन प्रक्रिया शुरू करने की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजस्थान माइनिंग सेक्टर से रेवेन्यू के क्षेत्र में भी अग्रणी



केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने गुरुवार को जयपुर में आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआईधारकों से बातचीत की।

प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने आवश्यक अनुमतियों प्रदान करने वाली संस्थाओं से व्यावहारिक रुख अपनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की वहीं प्रीएम्बेडेड की तर्ज पर ही पुरानी नीलाम खानों को परिचालन में लाने के लिए राज्य सरकार स्तर से भी सहयोग और मार्गदर्शन पर जोर दिया। उन्होंने एलओआईधारकों से भी आवश्यक औपचारिकता पूरी करने में अनावश्यक देरी नहीं करने का स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एलओआईधारकों से

संवाद कायम करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने बताया कि राजस्थान में 112 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। भविष्य में नीलाम होने वाले माइनिंग ब्लॉकों के नीलामी से पहले ही चरगाहा, वन कन्वर्जन आदि इसी तरह की आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए ब्लॉक बनाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे आवश्यक अनुमतियों प्राप्त करने में एलओआई धारक अनावश्यक

परेशानियों से बच सके। श्री रविकान्त ने बताया कि इस वर्ष 21 ब्लॉकों की सफल नीलामी हो चुकी है और 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों सहित 26 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विपुल और विविध प्रकार के खनिज संपदा वाला प्रदेश है। राज्य सरकार द्वारा माइनिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। नई खनिज नीति, एम. सेण्ड नीति के साथ ही प्रक्रिया को सरल

- भविष्य में नीलाम होने वाले माइनिंग ब्लॉकों के नीलामी से पहले ही चरगाहा, वन कन्वर्जन आदि इसी तरह की आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए ब्लॉक बनाने के प्रयास किए जाएंगे : टी. रविकान्त

किया गया है। इसके साथ ही एलओआईधारकों को सहयोग व मार्गदर्शन के लिए अलग से सेल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि एलओआईधारकों व संबंधित संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं वहीं निरन्तर मोनेटरिंग की जा रही है। केन्द्रीय खान उप सचिव आशीष सक्सेना, पीसीएफ पीके उपाध्याय, अरुण प्रसाद, सदस्य सचिव सीया विजय एन, निदेशक माईंस महावीर प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव माईंस अरविन्द सारस्वत, उप सचिव राजस्थान, आईबीएम के अभय अग्रवाल, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, एडीजी आलोक प्रकाश जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही एलओआईधारकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भजनलाल पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। चित्र में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मंच पर उपस्थित थे।

बिहार/जयपुर, 20 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बिहार के पटना में स्थित गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा को उपमुख्यमंत्री एवं अन्य सदस्यों को मंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार के निर्माण में संकल्पित होकर कार्य करेगी तथा बिहार में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। समारोह में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचन्द बैरवा तथा विधायक कुलदीप धनखंड सहित, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

डॉ. उमर उन नबी धुरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैंडलर्स से टेलीग्राम पर आए निर्देशों के अनुसार, बम बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपने नैटवर्क के स्टॉक में अमोनियम नाइट्रेट, जो एक शक्तिशाली विस्फोटक सामग्री है, को कई जगह जमा कर रखा था। अधिकारियों ने फरीदाबाद में लगभग 2,900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, टाइमर और अन्य सामग्री बरामद करने का दावा किया है।

जांच में मिली सीसीटीवी फुटेज से एक सुराग मिला है: हंडई आई-20 को दिल्ली ले जाने से पहले अल-फलाह मैडिकल कॉलेज के परिसर में 11 दिनों तक पार्क किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उसके बाद उमर ने, शायद अपने साथियों की गिरफ्तारी और उस पर बढ़ते दबाव में हताश होकर यह हमला करने का फैसला लिया। एक अधिकारी के अनुसार, “उसने यह सब प्लान किया और अपने दोस्तों के अरैस्ट होने के बाद इसे अंजाम दे दिया।

एन.आई.ए. और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक रूप से उमर उन-नबी को रेड फोर्ट ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध बताया है और इस घटना को

आतंकी हमला घोषित किया है। हालांकि कई महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि उन पर किस स्तर तक नियंत्रण था, जे.ई.एम. हैंडलर्स से उन्हें कितना सीधा निर्देश मिला और क्या वे वास्तव में आत्मघाती हमलावर थे, अब भी जांच के दायरे में हैं।

जांचकर्ताओं का यह भी कहना है कि जिस डिवाइस में धमाका हुआ, वह संभवतः उन्हीं सामग्रियों से बनाया गया था, जो फरीदाबाद से बरामद हुई थीं। इससे एक जुड़े हुए टैरर नेटवर्क की कड़ियां और मजबूत होती हैं। अभी सुरक्षा एजेंसियां मॉड्यूल की फंडिंग, उसके ऑपरेशन की पहुंच और पूरी लॉजिस्टिक श्रृंखला की जांच कर रही हैं। एक अधिकारी के अनुसार, “यह घटना उसी घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिससे एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ।”

अगर आरोप प्रमाणित होते हैं, तो उमर का मामला भारत के पेशेवर डॉक्टर वर्ग में कट्टरपंथी होने के सबसे गंभीर उदाहरणों में से एक होगा। एक कथित टैरर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में मैडिकल प्रैक्टिशनर्स का शामिल होना इस बारे में बड़े मुश्किल सवाल खड़े

करता है कि कैसे एक्स्ट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बहुत पढ़े लिखे, दिखने में सर्विस ओरिएन्टेड कम्युनिटीज में घुस सकती है। नई दिल्ली की एजेंसियों के सामने चुनौती न सिर्फ अदालत में टिकने वाला मजबूत मामला बनाने की है, बल्कि उन्हें यह भी तय करना है कि भविष्य में ऐसे वाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल को कैसे पहचाना और रोका जाए। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर हैं कि जांचकर्ता डॉ. उमर उन-नबी की पूरी कहानी को कैसे जोड़ते हैं।

‘पढ़े ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज् ने कहा कि अब डॉक्टरों और इंजीनियरों का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक ट्रेंड बन गया है। उन्होंने शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो कोर्ट में दिखाये। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए भी दिखाया गया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नीतीश कुमार के पारंपरिक समर्थन का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाजपा की उत्तर प्रदेश रणनीति इसी जनसांख्यिकी (डैमोग्राफी) पर टिकी हुई है। यूपी में कुर्मी वोटरों की संख्या बिहार की तुलना में लगभग दोगुनी है, और कई जिलों में यह समुदाय, दूसरे ओबीसी और ईबीसी समुदायों के साथ, पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा है।

अब भगवा पार्टी का मकसद यही है कि बिहार वाले जातीय संतुलन और अभीष्ट पहुंच (टांगेंट्स आउटरीच) को यूपी में दोहराकर इस वोट आधार में संघ लगाई जाए। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व यूपी में एक ताकतवर ओबीसी चेहरे को संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप

पंजाब पुलिस ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को अंजाम दे सकते थे। पंजाब पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के दो आतंकवादियों का

‘हमारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीडिया संस्थान को दबाने की कोशिश बताया। संपादक प्रबोध जमवाल और अनुराधा भसीन ने सोशल मीडिया पर जारी किये गये एक संयुक्त बयान में कहा कि “जम्मू कार्यालय पर छापे और हमारे खिलाफ निराधार आरोप एक बार फिर हमें चुप कराने की कोशिश है।”

उन्होंने कहा कि 1954 में वेद भसीन द्वारा स्थापित कश्मीर टाइम्स ने हमेशा स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखा है। “हमने इस क्षेत्र की सफलताओं और विफलताओं दोनों को समान मेहनत से दर्ज किया है। हमने उन समुदायों को आवाज दी है, जिनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। जब दूसरे चुप रहे, तब हमने कठिन सवाल पूछे।”

संपादकों ने कहा कि भले ही 2021-22 में “लगातार एवं निर्मम रूप से निशाना बनाए जाने” के बाद, अखबार का प्रिंट संस्करण बंद कर दिया गया था, लेकिन कश्मीर टाइम्स अब भी डिजिटल रूप से काम कर रहा है और उसका सारा काम उसकी वेबसाइट पर सबके लिये उपलब्ध है।

प. बंगाल में वामपंथी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नंदीग्राम में कार फैक्ट्री के लिए ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ उग्र आंदोलन करके उस जमे हुए सिस्टम को हिला दिया था।

जब वे सत्ता में आईं उन्हें पता था कि सिस्टम को कैसे मोड़ना है और गलत मतदाता सूचियों व वोटिंग में हेराफेरी के ज़रिये चुनावी जीत कैसे हासिल करनी है। अपने पहले कार्यकाल और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगे तगड़े झटके के बाद, उन्होंने एक ऐसा संरक्षण तंत्र खड़ा किया, जो पूरे बंगाल के सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में फैला हुआ है।

तृणमूल के ज़मीनी कार्यकर्ता आसानी से पहचाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनका पूरा विवरण मिल जाता है। वे अक्सर बहुत पतली सोने की चेन और दाढ़िने हाथ में वैंसा ही सोने का ब्रेसलैट पहनते हैं। बीच के स्तर के नेताओं के पास कई नई एसयूवी हैं और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के पास चमचमाती मोटरबाइकें।

वे तेजी से गाड़ी चलाते हैं और अक्सर मामूली सी बात पर भी अपनी कार से आम लोगों पर हमला कर देते हैं। हाल में न्यू टाउन इलाके में कार लेकर जा रहे आम लोगों पर, कार का स्पर्श करते हुये गुजरने पर भी, इसी तरह के हमले हुए, यहाँ तक कि उन लोगों

को उनके अपने गेटेड परिसर के अंदर तक पीटा गया। कई मायनों में, आम लोग, जो सत्ता पक्ष से जुड़े नहीं हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। यही लोग बूथ पर कब्जा करते हैं, फर्जी वोट डालते हैं और, आम तौर से, यह सुनिश्चित करते हैं कि विपक्ष के पक्ष में वोट पड़ ही न सके। नतीजतन, तृणमूल उम्मीदवार अक्सर रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। उदाहरण के लिए, ममता बनर्जी के मशहूर भतीजे ने देश में सबसे बड़े अंतर से जीत का रिकॉर्ड बनाया था। बंगाल में लोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से वोट डाल ही नहीं पाते, क्योंकि हर जगह तृणमूल के गुंडों का खतरा रहता है।

इसके अलावा, मृतक मतदाता सत्ताधारी पार्टी के लिए बड़ी मदद हैं। ऐसे मृत मतदाताओं के आँकड़ों को लेकर कई अनौपचारिक अनुमान और आँकड़े सामने आते रहते हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि लगभग 40 लाख मृत लोगों के नाम अभी भी जीवित मतदाता सूची में मौजूद हैं।

साथ ही, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा हैं। पहले लैपट फ्रंट के शासनकाल में इन्हें राज्य में घुसने में मदद दी जाती थी। तब ममता खुद इन अवैध प्रवासियों को कड़ी विरोधी थीं और संसद में यह मुद्दा कई बार उठाया था।

लेकिन सत्ता में आने के बाद, उन्होंने इसी साधन को और परिष्कृत रूप देकर, इन अवैध प्रवासियों को अपना प्रमुख एवं बड़ा वोट बैंक बना लिया। देशभर की रिपोर्टें बताती हैं कि पकड़ गए अधिकतर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के पास पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ इलाकों में बने आधार और वोटर कार्ड पाए जाते हैं। नवीनतम अनौपचारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि इन लोगों में डर फैल गया है। न्यू टाउन क्षेत्र, जहाँ पहली बार आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या ज्यादा रहती है, वहाँ बहुत सी झोपड़ियां और कमरे तालाबंद मिले हैं और उनमें रहने वाले लोग वापस बांग्लादेश लौट गए हैं। मुसलमान एसआईआर प्रक्रिया के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं और एक समय ममता ने वादा किया था कि वे इस प्रक्रिया को रोक देंगी। अब वही लोग ममता के खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि वे इसे रोकने में नाकाम रही हैं।

इसी वजह से ममता अब एसआईआर प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की मौतों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकने के नए तरीके खोज रही हैं। हो सकता है कि इस प्रक्रिया को बीच में रोकने के लिए वे किसी बड़े पैमाने की कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी को भी बढ़ावा दे दें।

थरूर ने अपनी ...

‘राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधानसभा से पारित विधेयक नहीं रोक सकते’

नयी दिल्ली, 20 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक फैसले में गुरुवार को कहा कि राज्य के राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। न्यायालय ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपालों को मंजूरी देने या न देने के लिए जरूरी समयसीमा तय नहीं कर सकता लेकिन राज्यपाल अनिश्चित काल तक किसी भी विधेयक को नहीं रोक सकते। हालांकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि लंबे समय तक, बिना किसी वजह के मंजूरी नहीं दिये जाने के मामलों में न्यायालय विधेयक की प्राथमिकता की जांच किए बिना एक निश्चित अवधि में फैसला करने का निर्देश देते हुए एक सीमित परमादेश रिट जारी कर सकते हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक्स पर एक पोस्ट में थरूर ने प्रधानमंत्री के मंगलवार के भाषण की तारीफ करते हुए लिखा कि “यह आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रेरणा, दोनों का मिश्रण था, जो राष्ट्र को प्रगति के लिए बेचैन रहने का आ न करता है।” यह प्रशंसा सामान्य लग सकती थी, अगर प्रधानमंत्री ने उसी भाषण में यह बात भी न कही होती कि “10-15 साल पहले कांग्रेस में घुसे शहरी नक्सल और माओवादी ताकतों ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बना दिया था, जिसने अब राष्ट्रीय हितों को छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए देश के हितों को छोड़ दिया है।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा: “आज माओवादी मुस्लिम कांग्रेस देश की एकता के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है।” कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने थरूर की टिप्पणियों से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के भाषण में कोई प्रशंसनीय बात नहीं लगी। कांग्रेस

नेता संदीप दीक्षित ने थरूर को पाखंडी बताते हुए कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री इतने योग्य लगते हैं, तो वे भाजपा में क्यों नहीं शामिल हो जाते? सी.पी.एम. के सांसद जॉन ब्रिट्टास ने भी थरूर पर जमकर हमला किया। उधर भाजपा इस विवाद का फ़ायदा उठाने में लगी है। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को “ईंदिरा नाज़ी कांग्रेस” कहा और पार्टी पर थरूर के खिलाफ एक और फ़तवा जारी करने का आरोप लगाया।

नीतीश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नड्डा, चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-एनडीए के कई अन्य शीर्ष नेता उपस्थित थे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुमार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

 **MARUTI SUZUKI**

NEXA

UPGRADE YOUR CELEBRATIONS WITH THE BALENO.
EFFECTIVE PRICE OF ₹ 5.67* LAKH



OFFER VALID TILL 30TH NOVEMBER

THE NEW AGE
BALENO
TECH GOES BOLD



360 VIEW CAMERA



HEAD UP DISPLAY



6 AIRBAGS AS STANDARD*



IN-BUILT SUZUKI CONNECT

3 years **100 000 km**
WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

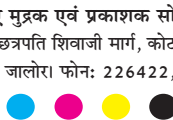


SCAN TO CONNECT TO
A SHOWROOM NEAR YOU

E-BOOK TODAY @
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at
1800-200-6392
1800-102-6392

*Ex. showroom Price of ₹ 5.98 899 lakh, Consumer Offer (-) ₹ 15 000, Exchange Bonus (-) ₹ 15 000, Rural Offer (-) ₹ 2 100 = ₹ 5.67 lakh. The actual Effective Price mentioned may vary based on the customer's eligibility, profile, and applicable offers at the time of purchase. T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. For details on safety features, refer owner's manual. NEXA dealers exclusively provide all offers, which vary by model and variant and city. Offers are subject to availability of stock. *Offer valid on BALENO SIGMA VARIANT till 30th Nov 2025. Not valid on CNG variants. Maruti Suzuki may withdraw offers without notice. Features and accessories shown can vary by variant. *3 years or 1 00 000 km, whichever is earlier. Finance is at the sole discretion of financier and subject to customer profile.



राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसेर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुघर्म एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुमाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डानसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डानसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908